

(b) Yes, Sir. According to the State Govt. of Manipur, they propose to strengthen the staff in the National Park for better protection and management.

रिहन्द जलाशय का प्रदूषण

2939. श्री जगन्नाथ सिंह: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय कोयला क्षेत्र लिमिटेड (एन.सी.एल.) सिंगरौली, मध्य प्रदेश में कार्यरत दस परियोजनाओं का विकास (स्यूरेंज), खदानों का विषाक्त पानि, मल-मूत्र और अपशिष्ट पदार्थ रिहन्द जलाशय में बहाकर जलाशय के पानी को प्रदूषित कर रहा है जिसके कारण जलाशय के जल-जन्तु मछली आदि एवं जलाशय से पय जल उपयोग में लाने वाले निवासियों को खतरा पैदा हो रहा है;

(ख) क्या इस संबंध में राष्ट्रीय कोयला क्षेत्र लिमिटेड (एन.सी.एल.) और विश्व बैंक को स्थानीय एन.जी.ओ. द्वारा निवेदन एवं अभ्यावेदन करने पर भी प्रदूषण मुक्त वातावरण प्रदान करने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा किये गये उपायों का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज): (क) मध्य- प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार रिहन्द जलाशय का पानी राष्ट्रीय कोलफील्डस, सिंगरौली द्वारा चलाई जा रही 10 परियोजनाओं के सीवेज एवं औद्योगिक बहिःस्त्राव के अन्तर्वाह के कारण संदूषित नहीं हो रहा है।

(ख) और (ग) उद्योगों को बहिःस्त्राव उपचार संयंत्र स्थापित करने के लिए निर्देश देते हुए जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्रावधानों के अन्तर्गत उपाय किए गए हैं।

पहाड़ी क्षेत्रों में दावानल के कारण वनों की हानि

2940. श्री महेश्वर सिंह: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस वर्ष पहाड़ी क्षेत्रों में, विशेषकर हिमाचल प्रदेश में दावानल व जंगलों में अन्य कारणों से आग लगने से करोड़ों रुपए के जंगल जलकर राख हो गए जिससे वन्यप्राणियों की भी भारी संख्या में जानें गई हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1996-97 में वन संपदा के जलने से कुल कितनी क्षति हुई;

(ग) क्या यह भी सच है कि हिमालय क्षेत्र में दावानल से निपटने के लिए हेलीकाप्टरों/वायुयानों का प्रावधान किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो कब और कितने हेलीकाप्टरों/वायुयानों का प्रावधान किया गया था और वर्तमान में इनका उपयोग कहां-कहां किया जा रहा है?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज): (क) और (ख) राज्यों से सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) और (घ) जैसाकि परियोजना में बल दिया गया है, प्रदर्शन, प्रशिक्षण और पायलट आपरेशन गतिविधियों के उद्देश्य से क्रमशः अक्तूबर 1986 और जुलाई, 1987 में यू.एन.डी.पी. से सहायता प्राप्त "आधुनिक दावानल नियंत्रण परियोजना" के तहत एक लामा हेलीकाप्टर और एक पाइपर सेनेका एयरक्राफ्ट उपलब्ध कराए गए।

पाइपर सेनेका-III फिक्सड विंग एयरक्राफ्ट 25.8.94 को सवाई माधोपुर (राजस्थान) के निकट हुई दुर्घटना में नष्ट हो गया और लामा हेलिकाप्टर तकनीकी कारणों से खड़ा है।

कुल्लू में गोविन्द बल्लभ पन्त हिमालयन डेवेलपमेंट इंस्टीट्यूट के अंतर्गत एक केन्द्र की स्थापना

2941. श्री महेश्वर सिंह: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में गोविन्द बल्लभ पंत हिमालयन डेवेलपमेंट इंस्टीट्यूट (जी.बी.पी.एच.डी.आई.) के अंतर्गत एक केन्द्र की स्थापना की गई है।

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त केन्द्र के कार्यालय एवं आवास के भवन अभी निर्माणाधीन हैं, यदि हां, तो कितना निर्माण कार्य हो चुका है और कब तक निर्माण कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा;

(ग) उक्त केन्द्र में किस-किस श्रेणी के कितने कर्मचारी और अधिकारी नियुक्त किए गए हैं और उनमें कितने स्थानीय (हिमाचली) हैं और किस-किस पद पर कार्यरत हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। अभी तक लगभग 60 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हुआ है और संभवतः अगस्त, 1997 तक निर्माण कार्य पूरा होगा।

(ग) इस केन्द्र में कर्मचारियों और अधिकारियों की नियुक्ति की वर्गवार कुल संख्या निम्नलिखित है:

वर्ग	संख्या
वैज्ञानिक-सी.	1
वैज्ञानिक-बी.	2
वैज्ञानिक-ए.	1
उच्च श्रेणी लिपिक	1
चालक	1
चपरासी	1

इनमें से एक चपरासी (परिचारक) हिमालय प्रदेश के कुल्लू जिले का है।

Guidelines for Clearance of New Industries

2942. SHRI S.M. KRISHNA: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) the details of parameters/guidelines laid down by Government for giving clearance for new industry or winding-up the established industry from pollution point of view;

(b) the details of industries, State-wise declared environmentally hazardous during last one year;

(c) whether Government have set-up monitoring cell to evaluate the project appraisal;

(d) if so, the details thereof and the details of industries, State-wise; and

(e) whether it is a fact that South Kannada district of Karnataka has been exempted from setting-up any industry, if so, the details thereof?

THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTS (PROF. SAIFUDDIN SOZ): (a) to (d) The Environmental Impact Assessment (EIA) Notification of 27.01.94 (as amended on 04.05.94) issued under the provisions of Environment (Protection) Act, (EPA) 1986 provides the procedure and guidelines for clearance of industrial projects listed in Schedule-I of the said Notification. Procedures have also been evolved for closing down industrial units under EPA for violation of pollution and environmental regulations. A multi-disciplinary Expert Committee has been constituted for environmental appraisal of projects. The details indicating state-wise break-up of hazardous installations are given in the enclosed statement. (See below).

(e) No, Sir.

Statement

State-wise Break-up of Hazardous Installations

S. No.	STATES/UNION TERRITORIES	NO OF NO. OF MAJOR	
		HAZARDOUS UNITS	ACCIDENT HAZARD (MAB) UNITS
1.	Andhra Pradesh	800	69
2.	Assam	7	07
3.	Bihar	740	34
4.	Goa	30	08
5.	Gujarat	2929	250
6.	Haryana	35	29
*7.	Himachal Pradesh	163	60
8.	Jammu & Kashmir	07	07
9.	Karnataka	600	27
10.	Kerala	1776	29